

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 93]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 8 मार्च 2017—फाल्गुन 17, शक 1938

चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2017

मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम  
( डिग्री/डिप्लोमा ) प्रवेश नियम, 2017

एफ-5-28-2017-1-पचपन.—

राज्य सरकार, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में शासकीय स्वशासी चिकित्सा  
महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.डी तथा एम.एस.) पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर  
डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.डी.एस)

पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

### नियम

#### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017" है ।

(ii) यह नियम शैक्षणिक सत्र 2017-18 से प्रवृत्त रहेंगे ।

#### 2. परिभाषाएं -इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(i) **NEET PG-2017** से अभिप्रेत है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एट्रेंस टेस्ट पी0जी0 2017 ।

(ii) **NEET MDS-2017** से अभिप्रेत है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एट्रेंस टेस्ट एम0डी0एस0 2017 ।

(iii) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है राज्य सरकार के अधीन शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय ।

(iv) "परीक्षा" से अभिप्रेत है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एट्रेंस टेस्ट पी0जी0 2017 (NEET PG-2017)/ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एट्रेंस टेस्ट एम0डी0एस0 2017 (NEET MDS-2017)

(v) "सीट" से आशय है, महाविद्यालयों में रिक्त/भरे स्थान ।

(vi) "सेवारत अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिनका नाम

- आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा इस बाबत जारी की गई सूची में हो ।
- (vii) "रिमोट एवं/या डिफकल्ट एरिया" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य के "89" अधिसूचित आदिवासी उपयोजना के विकास खण्डों में स्थित कोई भी क्षेत्र ।
- (viii) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अन्य पिछड़े वर्ग ।
- (ix) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अनुसूचित जातियाँ ।
- (x) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अनुसूचित जनजातियाँ ।
- (xi) "श्रेणी" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित श्रेणी ।
- (xii) "प्रवर्ग" से अभिप्रेत है विकलांग (पी.एच.) (जैसा कि भारत शासन श्रम मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट एवं निर्धारित है) एवं महिलाएं ।
- (xiii) "चयनित अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है ऐसे अभ्यर्थी जिनको परीक्षा की मैरिट सूची के आधार पर सीट आवंटित की गई है ।
- (xiv) "राज्य शासन" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन ।
- (xv) "जनजाति क्षेत्र" से अभिप्रेत है जनजाति उप योजना के अधीन क्षेत्र ।
- (xvi) "एम.सी.आई." से अभिप्रेत है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ।
- (xvii) "डी.सी.आई." से अभिप्रेत है डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया ।
- (xviii) "एम.पी.एम.सी." से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद ।
- (xix) "एम.पी.डी.सी." से अभिप्रेत मध्यप्रदेश दंत चिकित्सा परिषद ।
- (xx) "काउंसिलिंग" से अभिप्रेत है परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की मैरिट एवं पात्रता के अनुसार राज्य शासन द्वारा आयोजित सीट आवंटन की प्रक्रिया ।
- (xxi) "रजिस्टर्ड अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है काउंसिलिंग के लिये निर्धारित प्रक्रिया में रजिस्टर्ड पात्र अभ्यर्थी ।

- (xxii) "ऑल इण्डिया रिवरटेड सीटों" से अभिप्रेत है प्रदेश को वापस की जाने वाली ऑल इण्डिया कोटे की वह सीट जो ऑल इण्डिया काउंसिलिंग की अंतिम चरण की काउंसिलिंग के उपरान्त रिक्त रह गई हैं।
- (xxiii) "लेफ्ट आउट सीटों" से अभिप्रेत है अंतिम चरण की राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के उपरान्त किसी भी कारण से रिक्त रह गई सीट।
- (xxiv) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है ऐसा संस्थान जिससे प्रदेश के शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध हैं।

### 3. सामान्य—

- (i) स्नातकोत्तर डिग्री एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश एम.सी.आई. / डी.सी.आई. / विश्वविद्यालय / राज्य शासन / भारत सरकार/महाविद्यालय की स्वशासी संस्था की यथास्थिति, प्रवेश परीक्षा, सीट आवंटन तथा प्रवेश के दौरान समय-समय पर यथा संशोधित प्रवृत्त विनियमनों तथा नियमों में किये गए संशोधनों द्वारा शासित तथा विनियमित होंगे।
- (ii) प्रवेश की तारीख से, स्नातकोत्तर डिग्री की दशा में, तीन वर्ष की कालावधि के लिए स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा की दशा में, स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम दो वर्ष की कालावधि के लिए पूर्णकालिक होंगे। छात्र को संपूर्ण अध्ययनकाल में निजी प्रेक्टिस, अंशकालिक नौकरी या कोई अन्य नौकरी करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
- (iii) यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने प्रवेश परीक्षा के समय, स्कूटनी के समय/ प्रवेश के समय/प्रवेश के बाद किसी भी समय/अभिलेखों की छानबीन के समय कोई सुसंगत तथ्य छिपाए हैं और/या गलत जानकारी दी है तो अध्ययन के दौरान किसी भी समय उसका प्रवेश महाविद्यालय के अधिष्ठाता (डीन)/प्राचार्य द्वारा रद्द किया जा सकेगा एवं दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

(iv) दुराचरण, अनुशासनहीनता तथा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्रों के विरुद्ध, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का रद्द किया जाना सम्मिलित है। अनाधिकृत रूप से बिना पूर्व सूचना के निरंतर 45 दिन अनुपस्थित रहने पर प्रवेश निरस्तीकरण की कार्यवाही अधिष्ठाता/प्राचार्य के द्वारा गुण दोष के आधार पर की जायेगी। इस अनुपस्थिति अवधि का किसी भी प्रकार के मान्य अवकाश में समायोजन नहीं होगा। ऐसे प्रवेश के पश्चात् निष्कासित अभ्यर्थी, निष्कासन की तिथि से क्रमशः आगामी तीन वर्ष के लिये डिग्री कोर्स हेतु एवं आगामी दो वर्ष के लिये डिप्लोमा कोर्स हेतु राज्य के शासकीय स्वशासी एवं निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय की पी.जी. सीटों पर प्रवेश के लिये अपात्र होंगे तथा उन्हें आर्थिक दण्ड स्वरूप ₹ 10.00 लाख (₹ दस लाख) संबंधित महाविद्यालय की स्वशासी समिति के बैंक खाते में जमा कराने होंगे। बकाया राशि की वसूली भू-राजस्व बकाया के समान की जा सकेगी। उक्तानुसार राशि जमा किये जाने के पश्चात् ही संबंधित अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज वापस किये जायेंगे।

(v) राज्य शासन के विभागों द्वारा स्पांसर किये गये नियमित सेवारत अभ्यर्थियों को स्पांसरकर्ता मूल विभाग द्वारा वेतन प्रदाय किया जाएगा। संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों को वेतन प्रदायगी की पात्रता नहीं होगी। यह स्पांसरशिप पाठ्यक्रम फीस एवं किसी अन्य लाभ के लिये देय नहीं होगी, बल्कि ऐसे अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित फीस जमा करना अनिवार्य होगा। संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों को पीजी कोर्स के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा स्टायपेंड देय होगा।

(vi) काउंसिलिंग की प्रक्रिया कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा संपादित कराई जायेगी।

4. सीटों की उपलब्धता – शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध स्टेट कोटा की स्नातकोत्तर सीटों की जानकारी महाविद्यालयवार, पाठ्यक्रमवार (एम.एस./एम.डी./डिप्लोमा/एम.डी.एस), विषयवार एवं श्रेणीवार मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त पी.जी. काउंसिलिंग के लिये निर्धारित पोर्टल [www.dme.mponline.gov.in](http://www.dme.mponline.gov.in) पर उपलब्ध कराई जायेगी। इन सीटों को

परीक्षा में पात्र घोषित अभ्यर्थियों से ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से भरा जायेगा। सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है जो यथासमय निर्धारित पोर्टल [www.dme.mponline.gov.in](http://www.dme.mponline.gov.in) पर प्रकाशित किया जायेगा।

#### 5. आरक्षण:-

- (i) मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति (SC) के अभ्यर्थियों के लिए 16 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के अभ्यर्थियों के लिए (शासन द्वारा तत्समय प्रचलित निर्धारित क्रीमिलेयर को छोड़कर) 14 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेंगी। राज्य शासन द्वारा ऊपर उल्लेखित आरक्षण प्रतिशत में संशोधन किये जाने की स्थिति में संशोधित आरक्षण प्रतिशत लागू होगा।
- (ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर याचिका सिविल अपील क्रमांक 11270-11271 ऑफ 2016 (Arising out of SLP (C) No.13444-13445 of 2016) में पारित निर्णय दिनांक 25 नवंबर, 2016 के परिपालन में मेडिकल कॉंसिल ऑफ इण्डिया के पोस्ट ग्रेजुएट रेगुलेशनस, मेडिकल एजुकेशन-2000, अमेन्डेड अप टू जनवरी 2017 की कण्डिका 9 (VII) के अनुसार राज्य के ऐसे सेवारत अभ्यर्थी जिन्होंने रिमोट एण्ड/या डिफिकल्ट एरिया में कम से कम 3 वर्ष की सेवा दी हो (28 फरवरी 2017 की स्थिति में) हेतु सभी महाविद्यालयों में उपलब्ध स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की कुल सीट में से 50 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेंगी। ऐसी आरक्षित सीटों में से काउंसिलिंग के पश्चात् विभिन्न श्रेणियों में रिक्त रही सीटें संबंधित श्रेणी के ओपन गैर सेवारत अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी।
- (iii) महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक श्रेणी मैरिट-सह-विकल्प के अनुसार श्रेणीवार कुल सीट में से 30 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेंगी। यह आरक्षण विषयवार अथवा महाविद्यालयवार नहीं होगा।
- (iv) ऐसे अभ्यर्थी को जो मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, उन्हें काउंसिलिंग में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में स्थायी

जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । मध्य प्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल स्थायी जाति प्रमाण पत्र या मध्य प्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी होने संबंधी मूल प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण की पात्रता नहीं होगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा ।

- (v) ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी (PH) जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं और जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी के हैं, के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में तीन प्रतिशत सीटें (3%) प्रवेश हेतु श्रेणीवार आरक्षित रहेंगीं। यह आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) होगा। उक्त अभ्यर्थी को अपने प्रवर्ग के अतिरिक्त अपनी श्रेणी की ओपन सीटों में योग्यता के अनुसार आवंटन की पात्रता होगी।

**दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु सीट आवंटन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-**

- क) अनुसूचित जनजाति दिव्यांग – पात्रता देखने हेतु निम्नानुसार कम का पालन किया जायेगा । ओपन\* अनुसूचित जनजाति(ST OPEN) => अनुसूचित जनजाति दिव्यांग (ST PH) ।
- ख) अनुसूचित जाति दिव्यांग – पात्रता देखने हेतु निम्नानुसार कम का पालन किया जायेगा । ओपन\* अनुसूचित जाति(SC OPEN)=>अनुसूचित जाति दिव्यांग(SC PH)
- ग) अन्य पिछड़ावर्ग दिव्यांग— पात्रता देखने हेतु निम्नानुसार कम का पालन किया जायेगा । ओपन\* अन्य पिछड़ावर्ग (OBC OPEN) => अन्य पिछड़ावर्ग दिव्यांग (OBC PH)
- घ) अनारक्षित दिव्यांग – पात्रता देखने हेतु निम्नानुसार कम का पालन किया जायेगा । ओपन\* अनारक्षित (UR OPEN) => अनारक्षित दिव्यांग(UR PH) ।
- \*ओपन से आशय उस श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये उसी श्रेणी में आरक्षित सीट से भिन्न कोई सीट।

दिव्यांगों के इस आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर यह सीटें संबंधित श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी।

एम.सी.आई. के क्रमांक सं.भा.आ.प.-34 (41)

2008-मेडि/54469 दिनांक 25 मार्च, 2009 के निर्देशों के अनुसार दिव्यांगों हेतु सीट पहले 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत (PH-1) के बीच

निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी । 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत (PH-2) से कम तक के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों से यह सीट भरी जाएंगी । दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये मध्यप्रदेश राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सुनिश्चित विषयों की सीटें ही उपलब्ध रहेंगी।

(vi) दिव्यांगों के लिये आरक्षित सीटों पर प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को विहित प्रपत्र में जिला मेडिकल बोर्ड से वैध प्रमाणपत्र और अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांग व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से पात्रता प्रमाणपत्र, (दोनों) प्रस्तुत करने होंगे। अभिलेख सत्यापन (स्कूटनी) के समय दोनों मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवंटित सीट पर प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। जबलपुर से जारी पात्रता प्रमाण-पत्र काउंसिलिंग के प्रथम चरण प्रारंभ होने की तिथि से तीन माह की पूर्व की अवधि में जारी किया गया होना चाहिए।

(vii) "एम.सी.आई." द्वारा बनाए गये दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित दिव्यांगों को दिव्यांग प्रवर्ग में पात्रता नहीं होगी :-

- (क) हाथ/हाथों से विकलांग
- (ख) दृष्टि से विकलांग
- (ग) बहरापन
- (घ) 70 प्रतिशत से अधिक पैरों की विकलांगता।

(viii) राज्य कोटे के लिए ऑल इंडिया रिर्वेट सीटों की डिग्री पाठ्यक्रम की उपलब्ध सीटों की संख्या को गैर सेवारत अभ्यर्थियों की विभिन्न श्रेणियों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की उपलब्ध सीटों की संख्या को सेवारत एवं गैर सेवारत अभ्यर्थियों की विभिन्न श्रेणियों में उसी अनुपात में वितरित किया जाएगा जो म.प्र. शासन की आरक्षण नीति अनुसार राज्य कोटा की सीटों के लिए विहित है।



(ix) यदि आरक्षण के पात्र अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी में उपलब्ध नहीं होते हैं तो रिक्त सीट अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार उपलब्ध कराकर भरी जायेंगी :-

सर्वप्रथम अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को सीट आवंटन सुनिश्चित किया जायेगा। तदोपरान्त :

(क) 'अनुसूचित जनजाति श्रेणी' की रिक्त सीट पात्र 'अनुसूचित जाति श्रेणी' के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी। सीट आवंटन के लिये पात्रता देखने हेतु निम्नानुसार क्रम का पालन किया जायेगा :-

SC (OPEN) => SC (PH) => ST (OPEN) => ST (PH)

(ख) 'अनुसूचित जाति श्रेणी' की रिक्त सीट पात्र 'अनुसूचित जनजाति श्रेणी' के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी। सीट आवंटन के लिये पात्रता देखने हेतु निम्नानुसार क्रम का पालन किया जायेगा :-

ST (OPEN) => ST (PH) => SC (OPEN) => SC (PH)

(ग) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त सीटों को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा। सीट आवंटन के लिये पात्रता देखने हेतु निम्नानुसार क्रम का पालन किया जायेगा :-

OBC (OPEN) => OBC (PH) => SC (OPEN) => SC (PH) => ST (OPEN) => ST (PH)

(घ) अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त सीटों को अनारक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(ङ) उपरोक्त रीति में उपर उल्लेखित तीन आरक्षित श्रेणियों के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त सीटों को अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। सीट आवंटन के लिये पात्रता देखने हेतु निम्नानुसार क्रम का पालन किया जायेगा :-

UR(OPEN)=>UR(PH=>)OBC(OPEN)=>OBC(PH)=>  
SC(OPEN)=> SC(PH)=> ST (OPEN)=>ST(PH)

6. पात्रता :-

(i) NEET PG-2017/NEET MDS-2017 के घोषित परीक्षा परिणाम में निर्धारित कुल अंकों में से निम्नांकित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त अभ्यर्थी काउंसिलिंग के लिये पात्र माने जायेंगे :-

- क) अनारक्षित श्रेणी - 50th percentile या उससे अधिक
- ख) आरक्षित श्रेणी - 40th percentile या उससे अधिक
- ग) विकलांग अनारक्षित श्रेणी - 45th percentile या उससे अधिक

(ii) अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिये । मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी 3-7/2013/1/3 भोपाल दिनांक 20 मई 2015 ( विषय:- सामान्य प्रशासन विभाग की सेवा क्रमांक - कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में) के अनुसार मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र संबंधित जिला कलेक्टर या जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी होने पर ही मान्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा NEET PG-2017/ NEET MDS-2017 परीक्षा के आवेदन फार्म में मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी से संबंधित दिया गया विकल्प अंतिम माना जायेगा ।

अथवा

अभ्यर्थी द्वारा एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. की समस्त परीक्षाएं मध्यप्रदेश के चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालय से जो कि एम.सी.आई/डी.सी.आई. नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त हो, उत्तीर्ण की हों ।

अथवा

सेवारत अभ्यर्थी

- (iii) एम.सी.आई. के पोस्ट ग्रेज्युएट मेडिकल एज्युकेशन रेग्यूलेशन, 2000 संशोधित जनवरी, 2017 की कंडिका-9 (IV) के अनुसार सेवारत अभ्यर्थियों को दिये जाने वाले अनुभव अंकों के निर्धारण की प्रक्रिया एवं अनुभव अंक दिये जाने के निर्धारण का कार्य लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 28 फरवरी 2017 की स्थिति में किया जायेगा। सेवारत अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता एवं उपरोक्तानुसार परीक्षा में प्राप्तांकों में अनुभव अंकों को जोड़कर कुल प्राप्त अंकों के आधार पर सीट आवंटन की पात्रता होगी।
- (iv) सेवारत पुरुष अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा प्रवेश वर्ष की 1 जनवरी को 45 वर्ष होगी तथा महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
- (v) सभी पी0जी0 प्रवेशित अभ्यर्थियों को यथास्थिति मध्यप्रदेश राज्य की मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद/म0प्र0 दंत चिकित्सा परिषद से स्थाई पंजीकरण कराना आवश्यक है। पी0जी0 सीट आवंटन होने के पश्चात्, आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के एक माह के अन्दर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद/दंत चिकित्सा परिषद में पंजीकृत चिकित्सक होने हेतु आवेदन तथा संबंधित फीस जमा करने की पावती संबंधित महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगी अन्यथा प्रवेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- (vi) अभ्यर्थी को एम.सी.आई./डी.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से दिनांक 31 मार्च 2017 तक या इसके पूर्व अनिवार्य इंटर्नशिप (Compulsory Internship) पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
- (vii) कोई भी अभ्यर्थी जिसमें सेवारत अभ्यर्थी भी सम्मिलित हैं, ऑल इण्डिया कोटा अथवा स्टेट कोटे से आवंटित सीट पर अंतिम रूप से प्रवेशित होने के उपरान्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम छोड़ने की स्थिति में, पाठ्यक्रम छोड़ने की दिनांक से अथवा निष्कासन की स्थिति, में निष्कासन की दिनांक से तीन वर्ष स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम छोड़ने की स्थिति में डिप्लोमा छोड़ने की

दिनांक से अथवा निष्कासन की स्थिति में निष्कासन की दिनांक से दो वर्ष के लिये राज्य में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये पात्र नहीं होगा ।

- (viii) ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा स्नातकोत्तर डिग्री पूर्ण कर ली गई है, उन्हें पाठ्यक्रम पूर्ण करने की दिनांक से आगामी तीन वर्ष तक स्नातकोत्तर सीट पर प्रवेश की पात्रता नहीं होगी परन्तु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम 1 मई 2015 से 31 दिसम्बर 2016 तक की अवधि में पूर्ण कर लिया है, उन अभ्यर्थियों को केवल उसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु परीक्षा की मैरिट सूची के आधार पर पात्रता होगी। इस संबंध में अभ्यर्थी को स्कूटनी के समय इस आशय का घोषणा-पत्र (प्रोफार्मा-2) के अनुसार देना होगा ।
- (ix) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उनकी परीक्षा की ऑल इंडिया मैरिट के आधार पर मध्यप्रदेश में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय कोटे में प्रवेश दिया गया है तथा उनका चयन परीक्षा की मध्यप्रदेश स्टेट की मैरिट में भी हुआ है, वह मध्यप्रदेश कोटे के लिये आयोजित काउंसिलिंग में भाग लेने के लिये पात्र होंगे परन्तु वह अगर काउंसिलिंग में स्टेट कोटे में सीट का चयन करता है तो उसे अखिल भारतीय कोटे की सीट छोड़नी होगी।
- (x) मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रं. एफ 5-15/03/55/चिशि/1, दिनांक 26 दिसम्बर, 2003 के अनुसार शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेशित मध्यप्रदेश शासन की ग्रामीण सेवा के बाण्डेड छात्र, जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें उपयुक्तानुसार मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग अथवा चिकित्सा शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा तभी उन्हें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा ।
- (xi) अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के समय स्वयं उपस्थित रहकर सभी आवश्यक निम्न मूल दस्तावेज प्रोफार्मा-1 सहित प्रस्तुत करने होंगे:-

- (क) NEET PG-2017/NEET MDS-2017 परीक्षा की ऑल इंडिया रिजल्ट स्लिप एवं मय फोटो के परीक्षा के लिये जारी एडमिट कार्ड ।
- (ख) 10 वीं / 12 वीं बोर्ड परीक्षा की अंकसूची- आयु प्रमाण हेतु। (सेवारत अभ्यर्थियों के लिये)।
- (ग) एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. परीक्षाओं के अंतिम प्राफ (Prof) की अंक सूची ।
- (घ) अनिवार्य इन्टर्नशिप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट (Compulsory Internship completion certificate) अथवा दिनांक 31 मार्च, 2017 तक इन्टर्नशिप पूर्ण करने संबंधी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- (ङ) "एम.पी.एम.सी." / "एम.पी.डी.सी." का स्थायी / अस्थायी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र / स्थायी रजिस्ट्रेशन हेतु दिये गये आवेदन की पावती ।
- (च) स्नातकोत्तर अध्ययन से संबंधित घोषणा पत्र (प्रोफार्मा-2)।
- (छ) आधार कार्ड ।
- (ज) मध्यप्रदेश का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र ( यदि लागू हो)।
- (झ) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश राज्य में आरक्षित श्रेणी (जाति प्रमाण-पत्र) का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र ( यदि लागू हो)।
- (ण) वर्तमान वर्ष 2016-17 का तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की क्रीमी/नॉनक्रीमी लेयर के निर्धारण हेतु) (यदि लागू हो)
- (ट) प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी प्रायोजित (स्पांसरशिप) प्रमाण पत्र (सेवारत अभ्यर्थियों के लिए लागू)।
- (ठ) विकलांग प्रवर्ग हेतु जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र एवं विकलांग पुर्नवास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से जारी पात्रता प्रमाण-पत्र जो कि तीन माह से अधिक पुराना न हो ।
- (ड) म.प्र. शासन के ग्रामीण सेवा के लिए बांडेड अभ्यर्थियों को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/ चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।

## (xii) लेफ्ट आउट सीट के आवंटन हेतु पात्रता -

i) लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्र होंगे:-

- क) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व की काउंसिलिंग की चरणों में कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो ।
- ख) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व की काउंसिलिंग में ऑफ्ट फार वेटिंग (Opt for waiting) का ऑप्शन दिया है ।
- ग) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व के काउंसिलिंग चरणों में च्वाइस फिलिंग (choice filling) नहीं की है ।

ii) अर्थात् लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी अपात्र होंगे:-

- क) ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में उनको आवंटित सीट पर प्रवेशित हैं ।
- ख) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में उनको आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया है ।
- ग) ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के उपरान्त त्यागपत्र दिया गया है ।

7. फीस संरचना :-

प्रत्येक अभ्यर्थी (सेवारत् अभ्यर्थियों सहित) द्वारा नीचे वर्णित फीस नियमित रूप से संबंधित महाविद्यालय की स्वशासी समिति में जमा किया जाना होगी :-

- 1). शैक्षणिक फीस (डिग्री) ₹ 50,000/- प्रतिवर्ष
- 2). शैक्षणिक फीस (डिप्लोमा) ₹ 50,000/- प्रतिवर्ष
- 3). छात्रावास फीस ₹ 18,000/- प्रतिवर्ष
- 4). छात्र निधि ₹ 1,500/- प्रतिवर्ष
- 5). कॉशन मनी (बिना ब्याज के वापसी योग्य)- ₹ 3,000/- (प्रवेश के समय)
- 6). सुरक्षा निधि ( बिना ब्याज के वापसी योग्य)- ₹ 10,000/- (प्रवेश के समय)

8. फीस वापसी-

अखिल भारतीय कोटे व स्टेट कोटे से पीजी पाठ्यक्रम (डिग्री/ डिप्लोमा) में प्रवेशित छात्रों द्वारा स्टेट कोटे की अंतिम चरण की

काउंसिलिंग के अंतिम दिवस सांय 5:00 बजे तक सीट छोड़ने संबंधी सूचना लिखित में संबंधित महाविद्यालय में प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्रों द्वारा जमा वार्षिक शैक्षणिक शुल्क से 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि लौटाई जायेगी । उक्त समय-सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा जमा राशि वापिसी योग्य नहीं होगी । यह प्रक्रिया राज्य एवं राज्य के बाहर से प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होगी ।

#### 9. काउंसिलिंग कमेटी तथा काउंसिलिंग प्रक्रिया:-

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा प्रत्येक चरण की काउंसिलिंग एवं उसकी समस्त व्यवस्थाओं के लिये संचालक चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। समिति द्वारा समस्त अधिनिय विनियमनों एवं नियमों के अनुसार काउंसिलिंग की कार्यवाही की जाएगी। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा काउंसिलिंग प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।

#### काउंसिलिंग कमेटी की संरचना निम्नानुसार होगी-

1. संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश — अध्यक्ष
2. शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों के समस्त अधिष्ठाता, — सदस्य
3. शासकीय स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य — सदस्य
4. आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधि, जो प्राध्यापक स्तर के हों — सदस्य  
(संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश द्वारा नामांकित)
5. संचालक चिकित्सा शिक्षा में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी— सदस्य
6. मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के नामांकित प्रतिनिधि —सदस्य
7. संयुक्त संचालक कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश — सदस्य सचिव

10. प्रवेश— (i) अभ्यर्थी को काउंसिलिंग द्वारा विषय पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय आवंटित हो जाने के उपरान्त संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता (डीन) / प्राचार्य को अधिसूचित तारीख तथा समय पर प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा । इसके उपरान्त ही प्रवेश मान्य होगा।

(ii) अखिल भारतीय अथवा राज्य कोटे के अंतर्गत प्रवेश हो जाने पर अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित मूल दस्तावेज संबंधित महाविद्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा :—

(क) मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्/ मध्य प्रदेश दंत चिकित्सा परिषद् का स्थाई रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र, अथवा इस आशय का शपथ पत्र कि अभ्यर्थी 3 माह के अंदर मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्/ मध्य प्रदेश दंत चिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रेशन कराकर प्रवेशित संस्था में अनिवार्य रूप से जमा करेगा ।

(ख) मध्य प्रदेश शासन की ग्रामीण सेवा के लिये बॉडेड अभ्यर्थियों हेतु यथास्थिति लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

(ग) एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. डिग्री या एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. की अंतिम वर्ष की अंकसूची ।

संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य, अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये मूल दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी को जारी करेंगे ।

(iii) अखिल भारतीय एवं स्टेट कोटे पर प्रवेशित छात्रों को ग्रामीण सेवा का निर्धारित बंधपत्र पूर्ण करने अथवा बंध राशि जमा कर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही मूल दस्तावेज लौटाये जायेंगे ।

(iv) उम्मीदवार को अंतिम चरण की काउंसिलिंग एवं लेफ्ट आउट सीट के आवंटन में सीट आवंटन के पश्चात् महाविद्यालय में प्रवेश दिये जाने के बाद किसी भी आधार पर उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी ।

(v) ऐसे अभ्यर्थी जो निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश प्राप्त नहीं करते हैं अथवा प्रवेश के उपरान्त सीट से त्यागपत्र देते हैं, उनका प्रवेशित सीट



पर दावा समपहृत हो जाएगा तथा उन्हें दिया गया आवंटन/प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा तथा वह आगामी चरणों की काउंसिलिंग में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होंगे ।

- (vi) महाविद्यालयों के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा प्रत्येक चरण के प्रवेशित छात्रों की सूची कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को भेजी जायेगी तथा यह सूची संबंधित कालेज की वेबसाईट तथा नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी ।

**11. प्रवेशित छात्र निम्नलिखित के लिए हकदार होंगे (इसमें सेवारत अभ्यर्थी भी सम्मिलित हैं ) :-**

- (क) एक साप्ताहिक अवकाश (असंचयी)
- (ख) प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 19 दिवस के आकस्मिक अवकाश,
- (ग) अधिष्ठाता(डीन)/प्राचार्य की पूर्व अनुमति से, संपूर्ण शिक्षण अवधि के दौरान छात्रवृत्ति के साथ केवल 180 दिवस के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। चिकित्सा प्रमाणपत्र, प्रसूति अवकाश पर जाने के दस दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा [मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 5/123/2013/1/55 भोपाल दिनांक 03.06.2013 (परिशिष्ट- 01) एवं सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-7/1/2010/नि0/4 दिनांक 07/06/2010 (परिशिष्ट-1 ए)] ।
- (घ) मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 147/4572 /03/पचपन/चिशि-1, दिनांक 14.01.04 के अनुसार पूर्व अनुमति से, छात्रवृत्ति के बिना प्रतिवर्ष 15 दिवस का चिकित्सा अवकाश लेने की पात्रता होगी । बीमारी का चिकित्सा प्रमाणपत्र अवकाश पर जाने के पश्चात् 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा (परिशिष्ट 01 का बिन्दु क्रमांक 2)। यह अवकाश प्रतिवर्ष लिया जा सकेगा तथापि इसे किसी भी परिस्थिति में अन्य वर्षों के साथ संचय नहीं किया जा सकेगा । अवकाश पर जाने हेतु आवेदन संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष के माध्यम से कार्यालय अधिष्ठाता को देना होगा ।

## 12. बंध पत्र

### (क) ग्रामीण सेवा बंध पत्र:-

(i) सेवारत अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य चयनित अभ्यर्थियों (गैर सेवारत चयनित अभ्यर्थी- आल इण्डिया एवं स्टेट कोटा से प्रवेशित छात्रों) को, पी.जी. उपाधि (एमडी/एमएस)/ (एम डी एस)/ पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् निर्धारित एक वर्ष तक राज्य सरकार के अधीन शासन द्वारा निर्देशित स्थानों में कार्य करने के लिए शासन के अनुदेशों के अनुसार स्नातकोत्तर डिग्री के लिए ₹ 10.00 लाख (रु. दस लाख) तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए ₹ 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) का बंध पत्र (प्रोफार्मा क्रमांक 3) प्रवेश के समय निष्पादित करना होगा। शासकीय स्वशासी दंत/चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य, ऐसे अभ्यर्थियों की सूची, जो उनके संस्थान में स्नातकोत्तर परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, कम से कम 3 माह पूर्व तथा पी.जी. परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को उपलब्ध कराएंगे। आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं, ऐसे परिणाम में सफल अभ्यर्थियों को परिणाम घोषित होने के 3 माह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करेंगे।

(ii) मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 4-7/2010/1/55 दिनांक 25/08/2010 के अनुसार जिन स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों का चयन विभाग के अधीन शासकीय स्वशासी दंत/चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक/सीनियर रेसीडेंट/जूनियर रेसीडेंट/प्रदर्शक के पद पर हो जाता है, उन्हें ग्रामीण सेवा के बाण्ड/अधिसूचित क्षेत्र में सेवा के बाण्ड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जायेगा कि वे बाण्ड अवधि के बराबर अवधि तक उक्त महाविद्यालयों में सेवा करेंगे। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बाण्ड

की शर्त लागू हो जायेगी और उन्हें निर्धारित अथवा शेष रही अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होंगी ।

- (iii) सेवारत अभ्यर्थियों को पी0जी0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त डिग्री हेतु 05 वर्ष तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् 03 वर्ष की सेवा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विहित आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में देने हेतु निर्धारित प्रपत्र (प्रोफार्मा-4) पर बाण्ड का निष्पादित करना होगा जो पी0जी0 डिग्री हेतु ₹ 30.00 लाख ( तीस लाख) तथा पी0जी0 डिप्लोमा हेतु ₹ 20.00 लाख (बीस लाख) का होगा। बाण्ड का निष्पादन संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय के पक्ष में करना होगा । अधिष्ठाता को बाण्ड की एक प्रमाणित प्रति पैतृक विभाग को उपलब्ध करानी होगी ।
- (iv) अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज (नियम 10 (ii) में उल्लेखित) संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य के पास सम्पूर्ण बाण्ड अवधि के लिये जमा रहेंगे एवं बाण्ड की शर्तों के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपरान्त ही वापस किये जाएंगे ।
- (v) अगर कोई छात्र बाण्ड से मुक्त होना चाहता है तो ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय,खण्डपीठ, इंदौर द्वारा डब्ल्यू.पी.कमांक 11677/10 एवं अन्य प्रकरणों में पारित निर्णय अनुसार बाण्ड राशि महाविद्यालय की स्वशासी समिति के बैंक खातों में जमा कराकर बाण्ड से मुक्त हो सकता है । इसके लिये संबंधित अधिष्ठाता/प्राचार्य सक्षम होंगे । यदि कोई छात्र उच्च अध्ययन के लिये जाना चाहता है तो ऐसे छात्रों को बंधपत्र में उल्लेखित राशि की बैंक गारन्टी जिसकी अवधि डिग्री करने वाले अभ्यर्थियों के लिये 3 वर्ष एवं डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों के लिये 2 वर्ष होगी, संबंधित महाविद्यालय में जमा करना होगी। बैंक गारन्टी जमा करने पर उसे मूल दस्तावेज वापस किये जा सकेंगे। उच्च अध्ययन की समाप्ति पर छात्र को निर्धारित अथवा शेष रही ग्रामीण सेवा पूर्ण करना आवश्यक होगा । निर्धारित ग्रामीण सेवा पूर्ण करने के पश्चात् ही बैंक गारन्टी वापस की जाएगी तथा उपर उल्लेखित बैंक गारन्टी की वैधता अवधि के एक माह पूर्व

तक ग्रामीण सेवा पूर्ण न करने पर बैंक गारन्टी राजसात कर ली जाएगी । बैंक गारंटी का प्रारूप आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

**(ख) सीट लीविंग बॉन्ड (Seat Leaving Bond) :-**

- (i) ऑल इंडिया कोटे से आवंटित सीट पर प्रवेश के समय अभ्यर्थी को शपथ पत्र (प्रोफार्मा क्रमांक 5) प्रस्तुत करना होगा कि वह प्रवेशित सीट पर अध्ययनरत होकर पाठ्यक्रम पूर्ण करेगा तथा सीट लीविंग बाण्ड निष्पादित करना होगा कि यदि वह ऑल इंडिया काउंसिलिंग के अंतिम चरण के अंतिम दिन के पश्चात् अथवा उसके पश्चात पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पूर्व कभी भी किसी भी कारण से सीट से त्यागपत्र देता है अथवा उसे पाठ्यक्रम से निष्कासित किया जाता है तो वह आर्थिक दंड स्वरूप ₹ 10.00 लाख (रूपये दस लाख) संबंधित महाविद्यालय की स्वशासी समिति के बैंक खाते में जमा करेगा। यह राशि भू-राजस्व बकाया की तरह वसूल की जा सकेगी एवं तत्पश्चात् ही अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज वापस किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी त्यागपत्र देने की दिनांक से अथवा निष्कासन की दिनांक से कमशः आगामी तीन वर्ष एवं दो वर्ष के लिये राज्य की शासकीय/निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की पी.जी. सीट्स पर प्रवेश के लिये अपात्र होंगे ।
- (ii) स्टेट कोटे से आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को शपथ पत्र (प्रोफार्मा क्रमांक 5) प्रस्तुत करना होगा कि वह प्रवेशित सीट पर अध्ययनरत होकर पाठ्यक्रम पूर्ण करेगा तथा सीट लीविंग बाण्ड निष्पादित करना होगा कि यदि वह एम.पी.स्टेट कोटा पी0जी0 काउंसिलिंग के अंतिम चरण के अंतिम दिन के पश्चात् अथवा उसके पश्चात पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पूर्व कभी भी किसी भी कारण से सीट से त्यागपत्र देता है अथवा उसे पाठ्यक्रम से निष्कासित किया जाता है तो वह आर्थिक दंड स्वरूप ₹ 10.00 लाख (रूपये दस लाख) संबंधित महाविद्यालय की स्वशासी समिति के बैंक खाते में जमा करेगा। यह राशि भू-राजस्व बकाया की तरह वसूल की जा सकेगी एवं तत्पश्चात्

ही अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज वापस किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी त्यागपत्र देने की दिनांक से अथवा निष्कासन की दिनांक से कमशः आगामी तीन वर्ष एवं दो वर्ष के लिये राज्य की निजी/शासकीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की पी.जी. सीट्स पर प्रवेश के लिये अपात्र होंगे।

(iii) आवंटित सीट पर प्रवेशित सेवारत अभ्यर्थियों पर भी उपरोक्त सीट लीविंग बाण्ड लागू होगा (प्रोफार्मा क्रमांक-5)।

13. इन नियमों एवं काउंसिलिंग की प्रक्रिया में बदलाव का अधिकार मध्यप्रदेश शासन को होगा। बदलाव की सूचना कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश की वेबसाईट तथा काउंसिलिंग हेतु निर्धारित पोर्टल <https://dme.mponline.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी। अतः अभ्यर्थियों को कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) तथा <https://dme.mponline.gov.in> से सतत सम्पर्क में रहने की आवश्यकता होगी।

#### 14. नियमों का स्पष्टीकरण :-

- (i) इन नियमों के निर्वचन तथा संशोधनों से संबंधित किसी विवाद की स्थिति में, राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा तथा सभी संबंधितों पर आबद्धकर होगा।
- (ii) किसी भी विवाद की स्थिति में हिन्दी में प्रकाशित मध्यप्रदेश चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017 को ही मान्य किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भागीरथ सुनहरे, उपसचिव.

फोटो

**प्रमाण-पत्र/अभिलेखों की स्कूटनी, संबंधी प्रोफार्मा****प्रोफार्मा-1****भाग-अ (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)**

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने मध्य प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा /दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017 को भलीभांति पढ़ तथा समझ लिया है। मुझे म0प्र0 के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की जानकारी है। तत्पश्चात ही नियमों में दिये गये उपबंधों के अधीन काउंसिलिंग में भाग ले रहा/रही हूँ।

मैं काउंसिलिंग में भाग लेने के लिये मूल प्रमाणपत्र/ अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। यदि वांछित जानकारी नियमानुकूल नहीं है, या असत्य है या अधूरी है या निर्देशानुसार नहीं है तो ऐसा होने पर, यदि मुझे किन्हीं कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जाए।

- 1/ NEET PG-2017/NEET MDS-2017 परीक्षा का टेस्टिंग आई.डी.नं.....
- 2/ मेरिट सूची क्रमांक .....
- 3/ पूरा नाम: .....
- 4/ माता/पिता/पति/अभिभावक का पूरा नाम एवं पता .....
- 5/ श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/..... अन्य पिछड़ा वर्ग)
- 6/ प्रवर्ग- .....
- 7/ अभ्यर्थी का मोबाईल फोन नं. एवं ई-मेल आई.डी.नं.....
- 8/ अभ्यर्थी का बैंक खाता नं..... आई.एफ.एस.कोड नं..... पोर्टल पर नं.....

**मूल प्रमाण पत्र/अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे हैं उनके सामने सही (✓) का चिन्ह लगायें**

1. NEET PG-2017/NEET MDS-2017 परीक्षा की ऑल इंडिया रजिस्ट्रर स्लिप एवं मय फोटो के टेस्ट एडमिट कार्ड । ☐
2. 10 वीं /12 वीं बोर्ड परीक्षा की अंकसूची आयु प्रमाण हेतु। (सेवारत अभ्यर्थियों हेतु) ☐
3. एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. परीक्षाओं के अंतिम प्रोफ (Prof) की अंक सूची । ☐
4. अनिवार्य इन्टर्नशिप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट (Compulsory Internship completion certificate) अथवा दिनांक 31 मार्च, 2017 तक इन्टर्नशिप पूर्ण करने संबंधी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। ☐
5. एम.पी.एम.सी./एम.पी.डी.सी. का स्थायी/अस्थायी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र / स्थायी रजिस्ट्रेशन हेतु एम.पी.एम.सी./एम.पी.डी.सी.को दिये गये आवेदन की पावती । ☐
6. स्नातकोत्तर अध्ययन से संबंधित घोषणा पत्र । (प्रोफार्मा-2) ☐
7. अभ्यर्थी का आधार कार्ड । ☐

8. मध्यप्रदेश का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र ( यदि लागू हो) । ☐
9. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश राज्य में आरक्षित श्रेणी (जाति प्रमाण-पत्र) का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र ( यदि लागू हो) । ☐
10. वर्तमान वर्ष 2016-17 का तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की क्रीमी/नॉनक्रीमी लेयर के निर्धारण हेतु) (यदि लागू हो)। ☐
11. प्रायोजित (स्पांसरशिप) प्रमाण पत्र, (सेवारत अभ्यर्थियों के लिए लागू)। ☐
12. विकलांग प्रवर्ग हेतु जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र एवं विकलांग पुर्नवास केन्द्र,नेपियर टाउन, जबलपुर से जारी पात्रता प्रमाण-पत्र जो कि तीन माह से अधिक पुराना न हो (यदि लागू हो)। ☐
13. म.प्र. शासन की ग्रामीण सेवा के लिए बांडेड अभ्यर्थियों को यथास्थिति लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/ चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र । (यदि लागू हो)। ☐

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर के साथ पूरा नाम तथा पता

**फोटो**

## प्रमाण-पत्र/अभिलेखों की स्कूटनी, संबंधी प्रोफार्मा

### प्रोफार्मा-1

#### भाग-ब (स्कूटनी (छानबीन) समिति द्वारा भरा जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि स्कूटनी के समय उपस्थित अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर का राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित NEET PG-2017/NEET MDS-2017 में सम्मिलित परीक्षार्थियों के फोटो एवं हस्ताक्षर डाटा से मिलान करने के बाद सही पाया गया है अथवा भिन्नता पाई गई है ।

भिन्नता की स्थिति में टिप्पणी -.....

प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की जांच की गई तथा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियों के दो सेट रिकार्ड हेतु जमा कर लिये गये हैं।

सत्यापन के पश्चात्, अभ्यर्थी आवंटित सीट पर प्रवेश के लिये पात्र है

**अथवा**

निम्न अभिलेख/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण/या अन्य कारणों से आवंटित सीट पर प्रवेश के लिये पात्र नहीं है।

1. **NEET PG-2017/NEET MDS-2017** परीक्षा की ऑल इंडिया रिजल्ट स्लिप एवं मय फोटो के टेस्ट एडमिट कार्ड । ☐
2. 10 वीं /12 वीं बोर्ड परीक्षा की अंकसूची आयु प्रमाण हेतु। (सेवारत अभ्यर्थियों हेतु) ☐
3. एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. परीक्षाओं के अंतिम प्रोफ (Prof) की अंक सूची । ☐
4. अनिवार्य इन्टरनशिप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट (Compulsory Internship completion certificate) अथवा दिनांक 31 मार्च, 2017 तक इन्टरनशिप पूर्ण करने संबंधी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। ☐
5. एम.पी.एम.सी./एम.पी.डी.सी. का स्थायी/अस्थायी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र / स्थायी रजिस्ट्रेशन हेतु एम.पी.एम.सी./एम.पी.डी.सी.को दिये गये आवेदन की पावती । ☐
6. स्नातकोत्तर अध्ययन से संबंधित शपथ पत्र । (प्रोफार्मा-2) ☐
7. अभ्यर्थी का आधार कार्ड । ☐
8. मध्यप्रदेश का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र । (यदि लागू हो) ☐



9. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश राज्य में आरक्षित श्रेणी (जाति प्रमाण-पत्र) का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र । (यदि लागू हो) ☐
10. वर्तमान वर्ष 2016-17 का तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र ।  
(अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की क्रीमी/नॉन क्रीमी लेयर के निर्धारण हेतु ) (यदि लागू हो) ☐
11. प्रायोजित (स्पांसरशिप) प्रमाण पत्र, (सेवारत अभ्यर्थियों के लिए लागू) ☐
12. विकलांग प्रवर्ग हेतु जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र एवं विकलांग पुर्नवास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से जारी पात्रता प्रमाण-पत्र जो कि तीन माह से अधिक पुराना न हो । ☐
13. म.प्र. शासन के ग्रामीण सेवा के लिए बांडेड अभ्यर्थियों को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग / चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र । ☐

2. अपात्रता के कारण:-

प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर मय दिनांक,  
नाम  
पदनाम

**प्रोफार्मा-2**

फोटो

**NEET PG-2017/NEET MDS-2017 परीक्षा के माध्यम से प्रवेश हेतु  
पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाने वाला घोषणा-पत्र का प्रोफार्मा**

मैं, डॉ. ....आत्मज/आत्मजा.....

.....आयु..... निवासी .....  
सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि -

- वर्तमान में मैं मध्यप्रदेश राज्य में पिछले तीन वर्षों में यथा 2014,2015,2016 में मध्यप्रदेश पी.जी. काउंसिलिंग या आल इंडिया काउंसिलिंग द्वारा चयन के पश्चात् अध्ययनरत नहीं हूँ \* (विषय-.....में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को छोड़कर)
- पिछले तीन वर्षों के दौरान (2014, 2015, 2016) में मुझे म.प्र. राज्य में किसी भी विषय में म.प्र. स्टेट पी.जी. काउंसिलिंग या आल इंडिया काउंसिलिंग द्वारा कोई स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा \* (विषय-.....में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को छोड़कर) आवंटित नहीं किया गया है।
- गत दो वर्षों के दौरान (यथा 2015, 2016) में मैंने \* (विषय-.....में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को छोड़कर) कोई भी स्नातकोत्तर डिप्लोमा या गत तीन वर्षों के दौरान (2014, 2015, 2016) में कोई स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त नहीं की है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम .....

पता .....

**सत्यापन**

मैं, डॉ. ....आत्मज/आत्मजा.....

..... आयु ..... निवासी.....

सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि अनुक्रमांक 1 से 3 तक में दिये गये तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य हैं।

दिनांक .....

सत्यापनकर्ता व्यक्ति

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम .....

पता .....

- \* नोट:- ऐसे डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी जिन्हें नीट पी.जी. 2017 की मैरिट के आधार पर, स्टेट कोटा पी.जी. काउंसिलिंग- 2017 द्वारा जिस विषय में पी.जी.डिग्री पाठ्यक्रम आवंटित हुआ है पूर्व में यदि अभ्यर्थी द्वारा उसी आवंटित विषय में 01 मई, 2015 से 31 दिसम्बर 2016 तक की अवधि में पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण किया जा चुका है तो ऐसे अभ्यर्थी केवल इसी विषय के आवंटित पी.जी. डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

फोटो

**प्रोफार्मा - 3**  
**गैर सेवारत अभ्यर्थियों के लिये**  
**ग्रामीण सेवा बंध पत्र**

रुपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे  
मध्यप्रदेश के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों  
द्वारा ग्रामीण सेवा के संबंध में निष्पादित किये जाने वाले बंध पत्र का प्रारूप

1- मैं, ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी .....  
..... मध्यप्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में  
प्रवेश नियम 2017 के अंतर्गत प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ।  
2- मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2017 को पढ़कर भलीभांति समझ  
लिया है।

3- मैं सामान्य/आराक्षित श्रेणी की/का छात्रा/छात्र हूँ।

4- मैं एतद्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-

- अ. मैं चिकित्सा/दंत चिकित्सा, स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने के उपरान्त शासन द्वारा निर्देशित ग्रामीण क्षेत्रों  
में निर्धारित की गई अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा।  
ब. यह कि उपरोक्तानुसार शासन द्वारा निर्देशित स्थानों पर निर्धारित अवधि के लिये चिकित्सा सेवा करना मेरे लिये ब  
बंधनकारी रहेगा।  
स. मैं निम्न बातों के लिए अपनी सहमति प्रदान करती/करता हूँ :-

- (1) यह कि, मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों का पालन करने हेतु मैं  
वचनबद्ध रहूंगी/रहूंगा।  
(2) यह कि, निर्धारित अवधि (पी.जी. डिग्री पाठ्यक्रम हेतु अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु एक वर्ष की शासकीय  
सेवा शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर न करने की स्थिति में शासन को पी.जी. डिग्री हेतु रु० 10,00,000/-  
(रुपये दस लाख मात्र) अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु रु० 8,00,000/- (रुपये आठ लाख मात्र) का शासन  
को भुगतान करने का वचन देती/देता हूँ।

द. यह कि इस बंधपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में महाविद्यालय में जमा मूल दस्तावेज वापस प्राप्त  
करने का हकदार नहीं होऊंगा/होऊंगी।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :-

1.....  
2.....

प्रतिभूतिकर्ता

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी .....  
उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लेखित राशि के समकक्ष बैंक गारंटी अधिष्ठाता चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय के नाम  
जमा करूंगा जिससे बंधपत्र में उल्लेखित राशि वसूल की जा सकेगी।

हस्ताक्षर  
आवेदक/निष्पादनकर्ता

गवाह :-

1- .....

2- .....

फोटो

**प्रोफार्मा-4****सेवारत अभ्यर्थियों के लिये ग्रामीण सेवा प्रदान करने हेतु बंध-पत्र**

(रूपये 500/- के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे)  
मध्यप्रदेश के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा अधिसूचित सेवा के संबंध में निष्पादित किये जाने वाले बंध पत्र का प्रारूप

- 1- मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री..... निवासी .....  
..... मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम 2017 के अन्तर्गत प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ।
- 2- मैंने मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम 2017 को भलीभांती पढ़कर समझ लिया है।
- 3- मैं सामान्य/आरक्षित श्रेणीकी/का छात्रा/छात्र हूँ।
- 4- मैं। एतद् द्वारा यह बंध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-
  - अ. मैं चिकित्सा स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने के उपरांत शासन द्वारा निर्देशित आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में निर्धारित की गई अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा।
  - ब. यह कि उपरोक्तानुसार शासन द्वारा निर्देशित स्थानों पर निर्धारित अवधि के लिये चिकित्सा सेवा करना मेरे लिये बंधनकारी रहेगा।
  - स. मैं निम्न बातों के लिये अपनी सहमति प्रदान करती/करता हूँ:-
    - (1) यह कि, मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों का पालन करने हेतु वचनबद्ध रहूंगी/रहूंगा।
    - (2) यह कि, निर्धारित अवधि (पी.जी. डिग्री पाठ्यक्रम हेतु पाँच वर्ष तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु तीन वर्ष) की शासकीय सेवा शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर न करने की स्थिति मैं शासन को पी.जी. डिग्री हेतु रु. 30.00 लाख (रूपये तीस लाख) अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु रूपये 20.00 लाख (रूपये बीस लाख) का शासन को भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।
  - द. यह कि इस बंधपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में महाविद्यालय में जमा मूल दस्तावेज वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं होउंगा/होउंगी।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :-

- 1.....
- 2.....

**प्रतिभूतिकर्ता**

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री..... निवासी.....  
उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लेखित राशि के समकक्ष बैंक गारंटी अधिष्ठाता चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय के नाम जमा करूंगा जिससे बंधपत्र में उल्लेखित राशि वसूल की जा सकेगी।

हस्ताक्षर  
आवेदक निष्पादनकर्ता

गवाह :-

- 1.....
- 2.....

फोटो

**प्रोफार्मा - 5**

**गैर सेवारत एवं सेवारत अभ्यर्थियों के लिये**  
**(स्टेट कोटा एवं ऑल इण्डिया कोटे से प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)**  
**सीट लीविंग बंध-पत्र**

रुपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे

मध्यप्रदेश के शासकीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले सीट लीविंग बंध पत्र का प्रारूप

- 1- मैं, ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी ..... मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम 2017 के अंतर्गत प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ ।
- 2- मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2017 को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है ।
- 3- मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती/करता हूँ कि मेरे द्वारा मध्य प्रदेश स्टेट काउंसलिंग 2017 में भाग लेकर आवंटित सीट पाठ्यक्रम .....विषय .....तथा संस्था .....में प्रवेश लिया गया है ।
- 4- मैं एतद्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-
  - अ मैं चिकित्सा/ दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत अध्ययनरत रहकर पाठ्यक्रम पूर्ण करूंगा/करूंगी ।
  - ब यह कि, मेरे द्वारा अंतिम चरण की काउंसलिंग के अंतिम दिन के पश्चात् एवं पाठ्यक्रम पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में सीट से त्यागपत्र दिए जाने अथवा मेरा प्रवेश उपरांत संस्था के द्वारा निष्कासन किये जाने की स्थिति में, मैं संबंधित चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी समिति को सीट लीविंग बांड राशि रु0 10,00,000/- (रु0 दस लाख मात्र) भुगतान करने का वचन देता हूँ /देती हूँ ।
  - स- यह कि, सीट लीविंग बांड राशि रु0 10,00,000/- (रु0 दस लाख मात्र) जमा न करने की स्थिति में मुझे मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा मूल दस्तावेज वापस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा ।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :-

- 1.....
- 2.....

प्रतिभूतिकर्ता

मैं .....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....निवासी ..... उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लेखित राशि के समकक्ष बैंक गारंटी अधिष्ठाता चिकित्सा/ दंत चिकित्सा महाविद्यालय के नाम जमा करूंगा जिससे बंधपत्र में उल्लेखित राशि वसूल की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर  
आवेदक/निष्पादनकर्ता

गवाह :-

- 1- .....
- 2- .....

**मध्यप्रदेश शासन**  
**चिकित्सा शिक्षा विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

क्रमांक एफ-5-123-2013-1-55

भोपाल, दिनांक 3 जून 2013

प्रति,  
संचालक,  
चिकित्सा शिक्षा  
म. प्र. भोपाल.

**विषय:-** पी0जी0 छात्रों के अवकाश के संबंध में ।  
**सन्दर्भ:-** आपकी टीप क्रमांक 1192/पीजी/4/संचिधि/13 दि0 2/5/13

- 1- विषयातर्गत मध्यप्रदेश पी0जी0नियम 2012-13 के उप नियम-4 के अनुसार पी0जी0 छात्रों को निम्नानुसार अवकाश देय है :-  
(क) एक साप्ताहिक अवकाश (असंघयी)  
(ख) प्रति शैक्षणिक सत्र में 19 दिवस का आकस्मिक अवकाश  
(ग) डीन (अधिष्ठाता)/प्राचार्य की पूर्व अनुमति से सम्पूर्ण सेवा अवधि के दौरान छात्रवृत्ति के बिना 90 दिवस के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी । चिकित्सा प्रमाण-पत्र अवकाश पर जाने के दस दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।
- 2- मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 147/4572/03/पघपन/चिधि-1 दिनांक 14 जनवरी, 2004 के अनुसार पूर्व अनुमति, छात्रवृत्ति के बिना प्रतिवर्ष 15 दिवस का चिकित्सा अवकाश/बीमारी का प्रमाण-पत्र अवकाश पर जाने के पश्चात् 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।

उक्त नियमों के संबंध में निम्न निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

- (क) उपरोक्त बिन्दु 01 एवं 02 के अनुसार अवकाश अवधि को परीक्षा में बैठने हेतु उपस्थिति माध्य किया जाये, किन्तु उतनी अवधि का पृथक से वास्तविक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जिससे वास्तविक प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा ।
- (ख) साथ ही पी0जी0 डिग्री पाठ्यक्रम के लिये केवल 36 माह का ही स्टांयफण्ड तथा पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये केवल 24 माह का ही स्टांयफण्ड देय होगा ।
- (ग) उक्त प्रकार के प्रकरणों में यह व्यवस्था सुनिश्चित की जावे कि अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के उपरान्त ही घोषित हो ।
- (घ) पी0जी0 छात्रों को चिकित्सा अवकाश का आवेदन निर्धारित समय सीमा में संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष के माध्यम से अधिष्ठाता को प्रस्तुत करना होगा ।

(एस.एस.कुमरे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
भोपाल, दिनांक 16/6/2013

क्रमांक एफ-5/123/2013/1/55  
प्रतिलिपि:-

- 1- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/इंदौर/ग्यालियर/जयलपुर/सीवा की ओर सूचनार्थ ।
- 2- प्राचार्य, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर ।

(एस.एस.कुमरे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय

परिशिष्ट-1 एसंशोधित प्रसूति अवकाश नियम

सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ 1-7/1/2010/नि0/4 दिनांक 07/06/2010 के अनुसार प्रसूति अवकाश की पात्रता निम्नानुसार होगी :-

**प्रसूति अवकाश** - प्रसूति अवकाश की पात्रता 180 दिन की होगी । इस अवधि में अवकाश छात्रवृत्ति की पात्रता रहेगी ( जो वह अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व देय था) चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश पर जाने के 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा।